भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1150
05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएम-एबीएचआईएम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना

1150. श्रीमती हेमा मालिनीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत देश में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रावधान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त मिशन के अंतर्गत देश भर के ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों, किए गए व्यय और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार का ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को धनराशि का आवंटन बढ़ाने का विचार है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों (सीएस) के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसकी योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत उपाय, सभी स्तरों प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तर पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते है, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

योजना के सीएसएस घटकों के अंतर्गत, निम्नलिखित पाँच कार्यकलाप हैं जिनके लिए योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

i. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केंद्रों का निर्माण, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में जाना जाता है।
ii. शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (यू-एएएम) की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों और झुग्गी-झोपड़ियों जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
iii. ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना करना,
iv. देश में 730 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में एक ऐसी प्रयोगशाला होगी।
v. 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) स्थापित करना।

पीएम-एबीएचआईएम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक मानव संसाधनों को नियोजित करने और वेतन, उपभोग्य सामग्रियों, निदान और उपकरण रखरखाव जैसी आवर्ती लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों को व्यापक सहायता प्रदान करता है। यह गहन परिचर्या अवसंरचना, ऑक्सीजन प्रणाली, निदान और प्रयोगशाला उपकरणों के माध्यम से सुविधा केंद्रों को मजबूत करता है। बेहतर निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए आईटी अवसंरचना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र (एनडीएचई) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाया जाता है। ये उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ, उपकरण और डिजिटल क्षमता हो ताकि वे व्यापक और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखे जा सकते हैं:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/FINAL%20PM-ABHIM__15-12-21.pdf

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025 -26 तक योजना अवधि के दौरान 1,670 भवन-रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी-एएएम), 674 शहरी- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 515 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 75 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 74 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय **5,084.07 करोड़ रुपये** के प्रावधान किए गए हैं।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत मथुरा जिले के लिए स्वीकृतियां निम्नानुसार हैं:

जिले का नाम	भवन-रहित एसएचसी एएएम	शहरी-एएएम	बीपीएचयू	आईपी एचएल	सीसीबी
मथुरा	20	8	8	1	1

मथुरा जिले में 19 भवन रहित एसएचसी-एएएम, 3 शहरी-एएएम, 8 बीपीएचयू, 1 आईपीएचएल का कार्य पूरा हो चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य को पीएम-अभियान के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय निर्गत का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रू में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1.	2021-22	124.63	0.00
2.	2022-23	173.71	254.04
3.	2023-24	247.96	252.69
4.	2024-25	400.95	544.74

नोट: उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय निर्गत 08.07.2025 तक अद्यतन है और अनंतिम है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियों की जारी की गई राशि में वर्ष दर वर्ष लगातार वृद्धि हुई है।

*****